नव भारत

राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

हादसों में गई 6 की जान

क्रेन की मदद से शवों को निकाला, घने कोहरे के कारण हुआ हादसा

नवभारत न्यूज

ग्वालियर. सुबह घने कोहरे के बीच शुक्रवार को भिंड रोड हाइवे पर बंटू ढाबा के सामने तेज रफ्तार ट्रक ने कार को टक्कर मार दी. हादसे में कार सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं बालाघाट के परसवाड़ा क्षेत्र में हादसे में दो युवकों की मौत हो गई.

मृतकों की पहचान सौरभ शर्मा निवासी मेहगांव (भिंड), ज्योति यादव (भिंड), भूरे प्रजापति (गोरमी) भिंड और उमा राठौर पत्नी पति राम राठौर, निवासी मोरोली भिंड के रूप में हुई है.

सौरभ बीएससी एग्रीकल्चर का पेपर देने आगरा जा रहा था. कार उसके भाई की है. रास्ते में उसे ग्वालियर के लिए सवारी मिल थी, उसकी भी हादसे में मौत हो गई. सौरभ के भाई अंकित ने बताया कि सुबह

करीब 6 बजे सौरभ घर से निकला था. कोहरे की वजह से सुबह ग्वालियर में विजिबिलिटी 200 से 500 मीटर तक थी. ज्योति की बहन नीलम यादव ने बताया कि हमें सुबह सूचना मिली थी कि मालनपुर में एक्सीडेंट हुआ है. कार में मेरी बहन भी आ रही थी. उसे मथुरा जाना था, इसलिए वह गोरमी से निकली थी. उसके 2 बच्चे हैं. वह अकेली घर से निकली थी.

इधर, बालाघाट में दो बाइक सवारों की मौत

बालाघाट. किरनापुर थाना अंतर्गत परसवाड़ा क्षेत्र के देवगांव नदी के पास शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में दो बाइक सवार युवकों की मौत हो गई. सुबह 11 बजे हादसा उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बाइक से भिड़ंत हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार की भिड़ंत से बाइक सवार दोनों युवक सड़क से दूर जा गिरे. हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल दूसरे युवक को तत्काल उपचार के लिए किरनापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया.

चुन-चुन कर निकालेंगे घुसपैठिए

घुसपैठियों की संख्या शून्य से बढ़कर 64 लाख तक पहुंच गई : शाह

गुवाहाटी/डिब्रूगढ़, 30 जनवरी. असम में चुनावी सरगर्मी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों के मुद्दे पर विपक्ष को करारा जवाब दिया है. धेमाजी जिले के करेंग चापोरी में आयोजित मिसिंग यूथ फेस्टिवल के समापन समारोह में शाह ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल के दौरान अवैध घुसपैठ के कारण राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना में बड़ा बदलाव आया.

उन्होंने कहा कि घुसपैठियों की संख्या शून्य से बढ़कर 64 लाख तक पहुंच गई और सात जिलों में वे बहुमत की स्थिति में आ गए. शाह ने इसे असम की पहचान और सामाजिक संतुलन के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए ठोस कदम

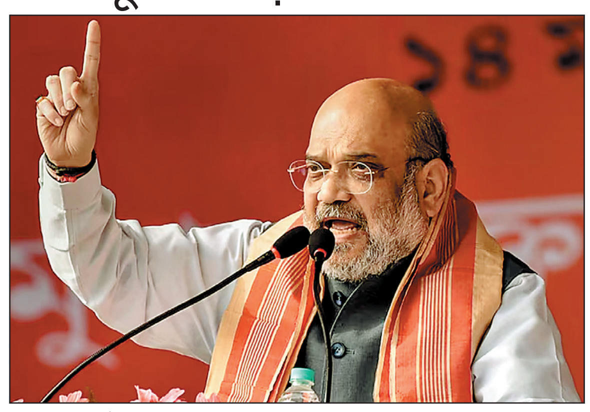

उठा रही है. उन्होंने राज्य में अतिक्रमण हटाने, भूमि मुक्त कराने और सीमावर्ती इलाकों में सख्ती बढ़ाने जैसे प्रयासों का भी जिक्र किया. साथ ही, आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा को तीसरे कार्यकाल के लिए समर्थन देने की अपील की, जिससे घुसपैठ की समस्या से निर्णायक तरीके से निपटा जा सके. शाह ने मिसिंग समुदाय की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि उनकी जीवनशैली ने ऊपरी असम में बाहरी बसावट को सीमित रखा है. शाह ने अपने संबोधन में कहा कि असम में घुसपैठ का मुद्दा नया नहीं है, बल्कि दशकों से चला आ रहा है. उनके अनुसार, कांग्रेस के शासनकाल में सीमा प्रबंधन और आंतरिक सुरक्षा को लेकर ढिलाई बरती गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि बड़ी संख्या में अवैध घुसपैठिए राज्य में बस गए. शाह ने दावा किया कि इस वजह से असम की डेमोग्राफी प्रभावित हुई और सात जिलों में सामाजिक संतुलन बदल गया.

> शाह ने मिसिंग समुदाय का विशेष उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी मेहनतकश जीवनशैली और सांस्कृतिक मजबूती के कारण ऊपरी असम में घुसपैठिए स्थायी रूप से बस नहीं पाए. उन्होंने कहा कि घुसपैठ रोकने के लिए हथियार उठाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी पहचान और परंपराओं को सशक्त बनाए रखना ही सबसे बड़ा उपाय है. साथ ही, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में कई आदिवासी समुदायों को अपनी पहचान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ा.

एक नजर में

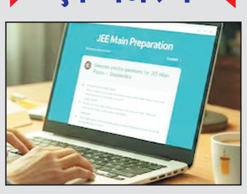

जेईई वालों के लिए गूगल लाया फ्री मॉक टेस्ट

नई दिल्ली. आईआईटी एस्पिरेंट्स और जेईई की तैयारी वालों के लिए गूगल ने बड़ी पहल की है. टॉप टेक कंपनी स्टूडेंट्स के लिए फ्री मॉक टेस्ट लेकर आई है. इससे वह अपनी जेईई की तैयारी शुरू कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं है. गूगल ने अपने जेमिनी ऐप पर जेईई मेन परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट पेपर जारी किए हैं. छात्र इन प्रैक्टिस टेस्ट को फ्री में एक्सेस कर सकते हैं. कंपनी ने जेईई मेन मॉक टेस्ट डेवलप किए हैं. ये टेस्ट पेपर असल जेईई परीक्षा के पैटर्न और फॉर्मेट जैसे ही हैं.

ट्रम्प की धमकी पर ईरान बोला- 1000 ड्रोन तैयार

तेहरान. अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की धमकी के बीच ईरान ने दावा किया है उसने जमीन और समुद्र से हमला करने वाले 1000 ड्रोन तैयार कर लिए हैं. ईरान की सेना ने दावा किया है अगर अमेरिका हमला करता है तो उसके ड्रोन और मिसाइलों को नेटवर्क इन हमलों को नाकाम कर सकता है. बता दें कि ट्रम्प ने 28 जनवरी को चेतावनी दी थी कि ईरान पर अगला हमला पहले से ज्यादा खतरनाक होगा.

भारत-यूरोपीय संघ समझौता देश के हितों की करता है रक्षा : मोदी

नई दिल्ली, 30 जनवरी (वार्ता) प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि हाल ही में हुआ भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के विजन से मेल खाता है. पीएम मोदी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया.

उन्होंने केन्द्रीय मंत्री पीयूष गोयल के इस समझौते के बारे में लिखे गए लेख को साझा करते हुए यह बात कही है. पीएम ने यह पोस्ट गोयल के पोस्ट पर प्रतिक्रिया स्वरूप लिखी. गोयल ने इस पोस्ट में भारत-ईयू समझौते के बारे में लिखे अपने लेख को साझा किया है. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि सरकार ने एक ऐसा परिवर्तनकारी समझौता किया है, जो बाजारों का विस्तार करता है, रोजगार पैदा करता है और भारत के मुख्य हितों की रक्षा करता है.

मप्र के प्रमुख सचिव रहे अरविंद जोशी की ईडी ने संपत्ति की कुर्क

भोपाल, 30 जनवरी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मध्य प्रदेश के प्रमुख सचिव रहे अरविंद जोशी की 5 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है. ईडी के भोपाल जोनल कार्यालय ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएम एलए) - 2002 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की. भोपाल लोकायुक्त की टीम ने इस मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित) की धारा 13(1)(ई) और 13(2) के तहत एफआईआर दर्ज की थी. मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा होने पर ईडी ने अपनी जांच शुरू की थी. इसमें जुलाई 1979 से 10 दिसंबर 2010 की अवधि के दौरान ज्ञात आय के स्रोतों से लगभग 41.87 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति जमा करने का आरोप था.

महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी सुनेत्रा, आज हो सकती है शपथ

नई दिल्ली, 30 जनवरी. अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हो गई हैं. सूत्रों के मुताबिक शनिवार को एनसीपी के विधायक दल की बैठक के बाद इसका ऐलान किया जाएगा. शाम 5 बजे शपथ ले सकती हैं. एनसीपी नेताओं में इस बात पर चर्चा चल रही है कि ये विभाग और पार्टी की नेशनल लीडरशिप किसे दी जाए. यह दावा भी किया जा रहा है कि अजित पवार एनसीपी के दोनों गुट के जिस मर्जर पर बातचीत कर रहे थे, उस पर आखिरी फैसला शरद पवार लेंगे. बता दें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की.

संविदाकर्मियों की भूमिका हनुमानजी के समान

संविदा कर्मचारी-अधिकारी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 30 जनवरी. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि संविदाकर्मियों के श्रम और विश्वास पर ही राज्य सरकार जनकल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने में सफल हो रही है. संविदाकर्मियों की भूमिका हनुमान जी के समान है. आपके श्रम और साझेदारी ने ही शासन-प्रशासन की व्यवस्था बनाई रखी है.

संविदाकर्मी अनुबंध से अवश्य आते हैं, किन्तु व्यवस्थाओं के प्रबंधन में विराट भूमिका निभाते हैं. स्वास्थ्य सेवाएं हों या शिक्षा, पंचायत, नगरीय निकाय या तकनीकी सेवाएं मैदानी स्तर पर सर्वे, मॉनीटरिंग और क्रियान्वयन में संविदा भाई-बहन हर जगह व्यवस्था के भरोसेमंद स्तंभ बनकर खड़े हैं. संविदाकर्मियों ने जिस निष्ठा से काम किया है, उसने यह सिद्ध कर दिया कि सेवा पद से बड़ी है. संविदाकर्मी राज्य सरकार का कार्यबल ही नहीं, हमारा आत्मबल भी हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को टीटी नगर दशहरा मैदान में भारतीय मजदूर संघ द्वारा आयोजित मप्र संविदा संयुक्त संघर्ष मंच के संविदा कर्मचारी-अधिकारी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इस दौरान मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि हमारी सरकार संविदा कर्मियों के अधिकारों के लिए सदैव सकारात्मक भाव के साथ खड़ी है. (शेष पेज 2 पर)

सुको का ऐतिहासिक फैसला बंद करें ऐसे स्कूल, जो बेटियों को न दे सकें सैनिटरी पैड

लड़के-लड़कियों के अलग टॉयलेट हों

नई दिल्ली, 30 जनवरी. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला सुनाया है. सुको ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे निजी और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को नि:शुल्क सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएं.

मामले में सख्ती बरतते हुए कोर्ट ने कहा कि जो स्कूल ऐसा नहीं कर सकती है, उन्हें बंद कर देना चाहिए. इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने कहा कि मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार संविधान में निहित जीवन के मौलिक

अधिकार का हिस्सा है.

जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों में छात्राओं तथा छात्रों के लिए अलग-अलग शौचालय सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया. कोर्ट ने ये भी कहा कि सभी स्कूलों को, चाहे वे सरकार द्वारा संचालित हों या सरकारी नियंत्रण में हों, दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल शौचालय उपलब्ध कराने होंगे.

सुको ने कहा, मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है. अदालत ने कहा कि अगर कोई प्राइवेट स्कूल ये सुविधाएं उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी.

2024 में लगाई गई थी याचिका

शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर, 2024 को जया ठाकुर द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इसमें स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी केंद्र सरकार की नीति को कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में अखिल भारतीय स्तर पर लागू करने की मांग की गई थी.